Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

भारत में बेरोजगारी और आर्थिक विकास: रोजगार सृजन की चुनौतियों एवं संभावनाओं का सैद्धांतिक अध्ययन

डॉ. इन्द्र सिंह

अर्थशास्त्र विभाग
दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, रामपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में रोजगार का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ तभी व्यापक रूप से दिखाई देता है जब उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कार्य करने योग्य जनसंख्या के लिए पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। बेरोजगारी केवल आय के अभाव की समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध गरीबी, आय-वितरण, उपभोग, बचत, सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन और आर्थिक विकास की गति से भी है। भारत जैसे विशाल और युवा जनसंख्या वाले देश में रोजगार सृजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करके रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भारत में बेरोजगारी की अवधारणा, उसके स्वरूप, प्रमुख कारणों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की स्थिति, शिक्षित एवं युवा बेरोजगारी, महिला श्रम सहभागिता, कौशल विकास तथा आर्थिक विकास के साथ रोजगार के संबंध का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रमुख आधार बनाया गया है। आधिकारिक वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में सामान्य स्थिति के आधार पर भारत की श्रम बल सहभागिता दर 60.1 प्रतिशत तथा कामगार जनसंख्या अनुपात 58.2 प्रतिशत रहा। इसी आधार पर बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत थी। 2017–18 में श्रम बल सहभागिता दर 49.8 प्रतिशत थी, जो 2023–24 में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हुई। महिलाओं की श्रम बल सहभागिता भी इसी अवधि में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई। नवीनतम 2025 के वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर श्रम बल सहभागिता दर 59.3 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 62.8 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 52.2 प्रतिशत रही।

मुख्य शब्द: बेरोजगारी, रोजगार, आर्थिक विकास, श्रम शक्ति, श्रम सहभागिता, युवा रोजगार, महिला रोजगार, कौशल विकास, भारत

1. प्रस्तावना एवं अध्ययन की पृष्ठभूमि

रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक विकास का मूल आधार है। व्यक्ति अपने श्रम के माध्यम से आय प्राप्त करता है और उस आय का उपयोग भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसी प्रकार श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसलिए रोजगार को केवल व्यक्तिगत आय प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता माना जाता है। जब कार्य करने की क्षमता और इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, तब उसकी श्रम क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत के संदर्भ में बेरोजगारी का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। भारत की जनसंख्या विशाल है और कार्यशील आयु की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश के लिए यह स्थिति एक अवसर भी है और चुनौती भी। यदि युवा जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित कौशल और पर्याप्त

रोजगार प्राप्त होता है, तो यही जनसंख्या आर्थिक विकास को तेज कर सकती है। युवा श्रमिक उत्पादन, उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी परिवर्तन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर यदि बड़ी संख्या में युवा रोजगार से बाहर रहते हैं अथवा उनकी शिक्षा और कौशल का उचित उपयोग नहीं हो पाता, तो देश की मानव पूँजी का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। बेरोजगारी की समस्या को केवल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से समझना उचित नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति सांख्यिकीय रूप से रोजगार में हो सकता है, लेकिन यदि उसकी आय बहुत कम है, रोजगार अस्थिर है, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है या उसकी योग्यता का उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसी कारण भारत के श्रम बाजार का अध्ययन करते समय रोजगार की मात्रा के साथ रोजगार की प्रकृति, नियमितता, आय और उत्पादकता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इस विषय में महत्वपूर्ण आँकड़े उपलब्ध कराता है। 2017–18 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए सामान्य स्थिति पर आधारित श्रम बल सहभागिता दर 49.8 प्रतिशत थी, जो 2023–24 में बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में पुरुषों की सहभागिता 75.8 प्रतिशत से बढ़कर 78.8 प्रतिशत तथा महिलाओं की सहभागिता 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि पहले की तुलना में अधिक लोग श्रम बाजार में भाग लेने लगे हैं। महिलाओं की श्रम सहभागिता में विशेष वृद्धि हुई है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। फिर भी पुरुषों और महिलाओं के बीच सहभागिता का अंतर काफी बड़ा है। इसलिए रोजगार नीति का उद्देश्य केवल बेरोजगारी घटाना नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उत्पादक और सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना भी होना चाहिए।

2. बेरोजगारी : अर्थ, अवधारणा एवं सैद्धांतिक आधार

सामान्य अर्थ में बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करने की क्षमता और इच्छा रखने के बावजूद उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। आर्थिक दृष्टि से यह श्रम बाजार में श्रम की उपलब्धता और रोजगार के अवसरों के बीच असंतुलन को दर्शाती है। किसी व्यक्ति का केवल काम न करना बेरोजगारी नहीं माना जाता; यह भी देखना आवश्यक है कि वह व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध है या नहीं तथा रोजगार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है या नहीं। बेरोजगारी के विभिन्न रूप होते हैं। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता। मौसमी बेरोजगारी में व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में यह समस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। छिपी बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति किसी कार्य में लगे रहते हैं और यदि कुछ व्यक्तियों को उस कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन में बहुत अधिक कमी नहीं आती। शिक्षित बेरोजगारी में व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता रखने के बावजूद अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। बेरोजगारी के संबंध में विभिन्न आर्थिक सिद्धांत अलग-अलग कारणों पर बल देते हैं। शास्त्रीय विचारधारा में श्रम बाजार में मजदूरी और श्रम की माँग एवं आपूर्ति के संबंध को प्रमुख माना गया। इसके विपरीत कीन्स के विचार में प्रभावी मांग की कमी को बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण माना गया। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कम हो जाती है, तो उत्पादक उत्पादन कम कर सकते हैं और रोजगार में कमी आ सकती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अर्थव्यवस्था की उत्पादन संरचना बदलती है और श्रमिकों के कौशल नई नौकरियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, तो रोजगार उपलब्ध होने के बावजूद बेरोजगारी बनी रह सकती है। तकनीकी परिवर्तन, स्वचालन, औद्योगिक पुनर्गठन तथा नई आर्थिक गतिविधियों का विस्तार इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रभावित कर सकता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इन सभी दृष्टिकोणों से प्रभावित होता है। यहाँ कृषि आधारित रोजगार, मौसमी रोजगार, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण-नगरीय अंतर, महिला सहभागिता तथा कौशल असंगति जैसी समस्याएँ एक साथ दिखाई देती हैं। इसलिए भारत में बेरोजगारी का समाधान किसी एक उपाय से संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षा, कौशल, उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और उद्यमिता को एक साथ मजबूत करना आवश्यक है।

3. भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति एवं प्रवृत्तियाँ

भारत में बेरोजगारी की स्थिति को समझने के लिए आधिकारिक श्रम बल सर्वेक्षण के आँकड़े अत्यंत उपयोगी हैं। 2017–18 से 2023–24 के बीच श्रम बाजार के प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। इस अवधि में श्रम बल सहभागिता दर

49.8 प्रतिशत से बढ़कर 60.1 प्रतिशत हुई। इसी प्रकार महिलाओं की श्रम सहभागिता 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या की श्रम सहभागिता 50.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.7 प्रतिशत हुई, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 47.6 प्रतिशत से बढ़कर 52.0 प्रतिशत हुई।

तालिका 1 : भारत में श्रम बल सहभागिता की प्रवृत्ति

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
2017–18	75.8%	23.3%	49.8%
2018–19	75.5%	24.5%	50.2%
2019–20	76.8%	30.0%	53.5%
2020–21	77.0%	32.5%	54.9%
2021–22	77.2%	32.8%	55.2%
2022–23	78.5%	37.0%	57.9%
2023–24	78.8%	41.7%	60.1%

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017–18 से 2023–24 तक कुल श्रम बल सहभागिता में निरंतर वृद्धि हुई। कुल सहभागिता 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 60.1 प्रतिशत हुई। लगभग 10 प्रतिशत अंक से अधिक की यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि कार्यशील आयु की अधिक जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों में शामिल हुई अथवा रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में आई। तालिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं की श्रम सहभागिता में वृद्धि है। 2017–18 में महिलाओं की सहभागिता केवल 23.3 प्रतिशत थी, जो 2023–24 में बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई। अर्थात लगभग छह वर्षों में महिलाओं की सहभागिता में 18 प्रतिशत अंक से अधिक की वृद्धि हुई। यह भारत के श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन है। हालांकि महिलाओं की सहभागिता अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, फिर भी वृद्धि की दिशा सकारात्मक है। पुरुषों की सहभागिता में भी वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि महिलाओं की तुलना में बहुत कम रही। इसका एक कारण यह है कि पुरुषों की सहभागिता पहले से ही अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर थी। इसके विपरीत महिलाओं की प्रारंभिक सहभागिता कम थी, इसलिए शिक्षा, ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार, कृषि गतिविधियों तथा अन्य आर्थिक अवसरों में वृद्धि के साथ इसमें अपेक्षाकृत तेज परिवर्तन दिखाई दिया। नवीनतम 2025 के वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधारित श्रम बल सहभागिता दर 59.3 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 62.8 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 52.2 प्रतिशत थी। इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत का श्रम बाजार पिछले वर्षों में अधिक सक्रिय हुआ है। फिर भी सहभागिता में वृद्धि के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त और उत्पादक रोजगार भी मिले।

4. ग्रामीण एवं नगरीय बेरोजगारी

भारत में ग्रामीण और नगरीय रोजगार बाजार की प्रकृति अलग-अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन तथा कृषि से संबंधित गतिविधियाँ रोजगार का महत्वपूर्ण आधार हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और अन्य सेवा गतिविधियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रमुख स्वरूप मौसमी बेरोजगारी है। कृषि कार्य पूरे वर्ष समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। बुवाई और कटाई के समय श्रम की माँग बढ़ जाती है, जबकि कृषि कार्य कम होने पर रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। इसी प्रकार छोटी जोतों वाले परिवारों में परिवार के अनेक सदस्य कृषि कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उनका अतिरिक्त श्रम उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करता। ऐसी स्थिति छिपी बेरोजगारी से जुड़ी होती है। नगरीय बेरोजगारी का स्वरूप अलग है। शहरों में शिक्षा प्राप्त और रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं की संख्या अधिक होती है। वे अक्सर अपनी योग्यता और अपेक्षित आय के अनुरूप रोजगार चाहते

हैं। इसलिए रोजगार मिलने में समय लग सकता है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी तथा कौशल असंगति अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण समस्याएँ बन सकती हैं।

तालिका 2 : 2023–24 में ग्रामीण और नगरीय श्रम बाजार के प्रमुख संकेतक

क्षेत्र	श्रम बल सहभागिता	बेरोजगारी दर
ग्रामीण	63.7%	लगभग 2.5%
नगरीय	52.0%	लगभग 5.0%
कुल	60.1%	3.2%

स्रोत: भारत सरकार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24।

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल सहभागिता नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इसका एक कारण कृषि तथा पारिवारिक आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण जनसंख्या की अधिक भागीदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति पारिवारिक कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय या अन्य गतिविधियों में लगा हो सकता है, जिसके कारण वह श्रम बाजार से पूरी तरह बाहर नहीं माना जाता। नगरीय क्षेत्रों में सहभागिता अपेक्षाकृत कम होने के साथ बेरोजगारी दर अधिक दिखाई देती है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि नगरीय श्रमिक औपचारिक अथवा अपेक्षाकृत बेहतर रोजगार की तलाश करते हैं और जब उपयुक्त अवसर उपलब्ध नहीं होता तो वे बेरोजगार बने रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विपरीत व्यक्ति कम उत्पादक या अस्थायी आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। इसलिए ग्रामीण और नगरीय बेरोजगारी की तुलना केवल बेरोजगारी दर के आधार पर करना उचित नहीं है। रोजगार की उत्पादकता, आय, नियमितता और सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ गैर-कृषि रोजगार बढ़ाना तथा नगरीय क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योग और सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देना दोनों ही आवश्यक हैं।

5. शिक्षित एवं युवा बेरोजगारी

शिक्षित बेरोजगारी भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षा के विस्तार से बड़ी संख्या में युवा उच्च विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति की क्षमता और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन यदि शिक्षा और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के बीच पर्याप्त तालमेल नहीं हो तो शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षित युवाओं की अपेक्षाएँ भी रोजगार की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अक्सर अपनी योग्यता के अनुरूप नियमित और अपेक्षाकृत अच्छी आय वाला रोजगार चाहता है। यदि उपलब्ध रोजगार उसकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता, तो वह रोजगार स्वीकार करने के बजाय आगे रोजगार की तलाश कर सकता है। इस कारण शिक्षित बेरोजगारी की दर सामान्य बेरोजगारी की तुलना में अधिक दिखाई दे सकती है। 2025 के वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 2024 में 7.0 प्रतिशत से घटकर 2025 में 6.5 प्रतिशत हुई। (Ministry of Statistics) यह सुधार सकारात्मक है, लेकिन 6.5 प्रतिशत की दर यह दर्शाती है कि शिक्षा और रोजगार के बीच अभी भी बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। युवा बेरोजगारी का प्रभाव दीर्घकालीन भी हो सकता है। यदि किसी युवा को शिक्षा पूरी करने के बाद लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता, तो उसके कौशल का व्यावहारिक उपयोग नहीं हो पाता। कार्य अनुभव में देरी होने से भविष्य के रोजगार अवसर और आय क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए युवाओं को केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्र देना पर्याप्त नहीं है; उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव और रोजगारोन्मुख कौशल भी प्रदान करना आवश्यक है। भारत में युवा रोजगार के लिए शिक्षा संस्थानों और रोजगार बाजार के बीच संबंध मजबूत करना आवश्यक है। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, उद्योग आधारित अनुभव, समस्या समाधान, संचार क्षमता और अंकीय दक्षता को शामिल करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा से रोजगार की ओर जाने में सहायता मिल सकती है।

6. महिला रोजगार एवं श्रम सहभागिता

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कार्य करने योग्य महिलाओं का बड़ा हिस्सा श्रम बाजार में शामिल नहीं होता, तो देश की कुल मानव पूँजी का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। महिलाओं की रोजगार सहभागिता बढ़ने से परिवार की आय बढ़ सकती है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ सकता है तथा परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। भारत में पिछले वर्षों में महिला श्रम सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2017–18 में सामान्य स्थिति के आधार पर महिलाओं की श्रम बल सहभागिता 23.3 प्रतिशत थी, जो 2023–24 में बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.6 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 28.0 प्रतिशत हुई। यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। 2023–24 में पुरुषों की कुल श्रम सहभागिता 78.8 प्रतिशत थी, जबकि महिलाओं की 41.7 प्रतिशत। (Ministry of Statistics) इस अंतर को केवल रोजगार के अवसरों की कमी से नहीं समझा जा सकता। घरेलू जिम्मेदारियाँ, बच्चों की देखभाल, सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल की सुरक्षा, सामाजिक मान्यताएँ और उपयुक्त कार्य की उपलब्धता भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

महिला रोजगार बढ़ाने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, बाल देखभाल सुविधाएँ, कौशल विकास, लचीली कार्य व्यवस्था और महिलाओं के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधाएँ आवश्यक हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूह, छोटे व्यवसाय और सेवा आधारित रोजगार विकसित किए जा सकते हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि को केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। अधिक महिलाएँ उत्पादक गतिविधियों में शामिल होंगी तो देश की कुल उत्पादन क्षमता और परिवारों की आय दोनों बढ़ सकते हैं।

7. बेरोजगारी के प्रमुख कारण एवं आर्थिक प्रभाव

भारत में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं और इनका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक वर्गों पर अलग-अलग पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। यदि रोजगार सृजन की गति रोजगार चाहने वाली जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप नहीं रहती, तो बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा और रोजगार के बीच असंगति भी महत्वपूर्ण कारण है। अनेक युवा सामान्य शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन रोजगार बाजार में तकनीकी तथा व्यावहारिक कौशल की माँग अधिक होती है। इससे एक ओर शिक्षित बेरोजगारी और दूसरी ओर उद्योगों में कुशल श्रमिकों की कमी एक साथ दिखाई दे सकती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी समस्या है। यदि बड़ी संख्या में लोग कम उत्पादक कृषि गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं, तो श्रम उत्पादकता कम रह सकती है। कृषि से जुड़े रोजगार को खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और ग्रामीण उद्योगों से जोड़कर श्रम उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तकनीकी परिवर्तन भी रोजगार की प्रकृति बदल रहा है। नई तकनीक कुछ पारंपरिक कार्यों की आवश्यकता कम कर सकती है, लेकिन साथ ही नए रोजगार भी उत्पन्न करती है। इसलिए तकनीकी परिवर्तन को रोजगार के लिए केवल खतरा मानने के बजाय कौशल विकास के साथ जोड़ना आवश्यक है।

बेरोजगारी का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव संभावित उत्पादन की हानि है। यदि कार्य करने योग्य व्यक्ति उत्पादन में शामिल नहीं होते, तो देश अपनी संभावित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। बेरोजगारी परिवार की आय और उपभोग को भी प्रभावित करती है। आय कम होने पर परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं पर कम खर्च कर सकता है। दीर्घकालीन बेरोजगारी मानव पूँजी को भी प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक काम न मिलने से व्यक्ति का कौशल अप्रयुक्त रह सकता है और भविष्य में रोजगार प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए बेरोजगारी को केवल वर्तमान आय की समस्या नहीं बल्कि भविष्य की उत्पादक क्षमता से जुड़ी समस्या भी माना जाना चाहिए।

8. आर्थिक विकास, रोजगार एवं कौशल विकास का संबंध

आर्थिक विकास और रोजगार के बीच सामान्यतः सकारात्मक संबंध होता है। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, तो उद्योगों, व्यापारिक संस्थाओं और सेवा क्षेत्रों में श्रम की माँग बढ़ सकती है। लेकिन यह संबंध स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। यदि आर्थिक वृद्धि मुख्यतः पूँजी और अत्यधिक तकनीक आधारित हो, तो उत्पादन में वृद्धि के बावजूद रोजगार की वृद्धि सीमित हो सकती है।
भारत के लिए रोजगार प्रधान आर्थिक विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें कृषि से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करते हैं, तो आर्थिक विकास अधिक समावेशी हो सकता है। कौशल विकास इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। आधुनिक रोजगार बाजार में केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त नहीं है। तकनीकी ज्ञान, समस्या समाधान, संचार क्षमता, अंकीय दक्षता, प्रबंधन क्षमता और कार्यस्थल संबंधी व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में रोजगार और कौशल विकास को अलग प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में श्रम बाजार की बदलती आवश्यकताओं और कौशल विकास के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण का वास्तविक परिणाम रोजगार, आय और उत्पादकता में दिखाई देना चाहिए। इसके लिए उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत संबंध आवश्यक हैं। प्रशिक्षुता व्यवस्था को मजबूत करके युवाओं को शिक्षा के साथ वास्तविक कार्य अनुभव दिया जा सकता है।

9. रोजगार सृजन में कृषि, उद्योग, सेवा एवं उद्यमिता की भूमिका

भारत में कृषि अभी भी रोजगार का एक प्रमुख आधार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ राष्ट्रीय आय में लगभग एक-पाँचवाँ योगदान देती हैं, जबकि देश के कार्यबल का लगभग 46.1 प्रतिशत इन गतिविधियों में संलग्न है। यह स्थिति दर्शाती है कि कृषि में रोजगार की संख्या बड़ी है, लेकिन कृषि की उत्पादकता और आय बढ़ाने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कृषि से जुड़े रोजगार को अधिक उत्पादक बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, भंडारण और कृषि विपणन का विस्तार किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त रोजगार भी उत्पन्न होंगे और किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आएगी। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, फर्नीचर, निर्माण सामग्री और अन्य श्रम प्रधान उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर सकते हैं। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्त, तकनीक, बाजार और आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ तथा अंकीय सेवाएँ रोजगार के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार 2025–26 की पहली छमाही में कार्यबल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा तृतीयक क्षेत्र में था।
उद्यमिता भी रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि युवा केवल नौकरी खोजने के बजाय छोटे व्यवसाय और नए उद्यम स्थापित करते हैं, तो वे स्वयं रोजगार प्राप्त करने के साथ अन्य व्यक्तियों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुँच और सरल व्यावसायिक प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं। इस प्रकार भारत में रोजगार सृजन के लिए कृषि, उद्योग, सेवा और उद्यमिता को अलग-अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में विकसित करना चाहिए।

10. भारत में रोजगार संबंधी सरकारी प्रयास एवं उनका महत्व

भारत सरकार ने रोजगार, ग्रामीण आजीविका, कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को निश्चित अवधि के लिए मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है। यदि प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार अवसरों से जोड़ा जाए तो इसका प्रभाव अधिक प्रभावी हो सकता है। स्वरोजगार और उद्यमिता

से संबंधित सरकारी प्रयास भी रोजगार सृजन में योगदान कर सकते हैं। छोटे व्यवसायों को ऋण, प्रशिक्षण तथा बाजार सहायता मिलने पर वे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर बढ़ाना उपयोगी हो सकता है। सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल लाभार्थियों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना आवश्यक है कि कार्यक्रम से प्राप्त रोजगार कितना स्थायी है, उससे कितनी आय प्राप्त हो रही है, क्या कौशल का उपयोग हो रहा है और क्या व्यक्ति भविष्य में स्वतंत्र रूप से रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसलिए रोजगार नीति में संख्या के साथ गुणवत्ता, स्थायित्व, आय और सामाजिक सुरक्षा को भी शामिल करना आवश्यक है।

11. द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण एवं विस्तृत व्याख्या

तालिका 3 : 2025 में भारत के श्रम बाजार की स्थिति

संकेतक	भारत	ग्रामीण	नगरीय
श्रम बल सहभागिता दर	59.3%	62.8%	52.2%
15–29 वर्ष आयु की श्रम बल सहभागिता	46.0%	47.3%	43.1%
पुरुष श्रम बल सहभागिता	79.1%	—	—
महिला श्रम बल सहभागिता	40.0%	—	—

स्रोत: भारत सरकार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025।

तालिका से स्पष्ट है कि 2025 में भारत की कुल श्रम बल सहभागिता दर 59.3 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 62.8 प्रतिशत थी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 52.2 प्रतिशत। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सहभागिता का संबंध कृषि, पारिवारिक व्यवसाय और अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से हो सकता है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की प्रकृति अधिक औपचारिक तथा प्रतिस्पर्धी होने के कारण श्रम बाजार में प्रवेश की स्थिति अलग दिखाई देती है। (Ministry of Statistics) 15–29 वर्ष की युवा जनसंख्या में श्रम बल सहभागिता 46.0 प्रतिशत रही। ग्रामीण युवाओं में यह 47.3 प्रतिशत तथा नगरीय युवाओं में 43.1 प्रतिशत थी। यह आँकड़ा बताता है कि युवाओं का लगभग आधा हिस्सा ही श्रम बाजार में सक्रिय रूप से शामिल था। इसका एक कारण शिक्षा में भागीदारी भी हो सकता है, क्योंकि युवा आयु वर्ग का एक बड़ा भाग अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। पुरुषों की श्रम बल सहभागिता 79.1 प्रतिशत तथा महिलाओं की 40.0 प्रतिशत रही। यह अंतर भारत की रोजगार नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में निरंतर वृद्धि होती है, तो देश की उपलब्ध मानव पूँजी का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकता है। महिला रोजगार बढ़ने से परिवार की आय तथा आर्थिक सुरक्षा में भी सुधार हो सकता है।

2025 के आँकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में श्रम बाजार की स्थिति को केवल बेरोजगारी दर से नहीं समझना चाहिए। सहभागिता, रोजगार की प्रकृति, कार्य की नियमितता और श्रमिकों की उत्पादकता को एक साथ देखने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार 2025–26 की पहली छमाही में कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 39.5 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 42.4 प्रतिशत हुई, जबकि द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 26.6 प्रतिशत से घटकर 24.2 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.9 प्रतिशत से घटकर 33.5 प्रतिशत हुई। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में रोजगार संरचना अभी भी कृषि पर काफी निर्भर है। दीर्घकाल में आर्थिक विकास को अधिक उत्पादक बनाने के लिए श्रमिकों को उच्च उत्पादकता वाले उद्योगों और सेवाओं की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी।

12. प्रमुख चुनौतियाँ एवं नीतिगत सुझाव

भारत के सामने रोजगार सृजन की पहली बड़ी चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में युवा प्रत्येक वर्ष रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। इसलिए वर्तमान बेरोजगारी कम करना पर्याप्त नहीं है। भविष्य में श्रम बाजार में आने वाले नए युवाओं के लिए भी पर्याप्त

अवसर उत्पन्न करने होंगे। दूसरी चुनौती रोजगार की गुणवत्ता है। केवल किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। रोजगार से पर्याप्त आय, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और भविष्य की आर्थिक स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए नीतियों में नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और उत्पादक रोजगार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरी चुनौती महिलाओं की कम श्रम सहभागिता है। यद्यपि महिलाओं की सहभागिता में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी पुरुषों की तुलना में अंतर बड़ा है। सुरक्षित कार्यस्थल, बाल देखभाल, परिवहन, लचीली कार्य व्यवस्था और महिला उद्यमिता के माध्यम से इस अंतर को कम किया जा सकता है। चौथी चुनौती कृषि पर रोजगार की अधिक निर्भरता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कार्यबल का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि में है।) कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार का विस्तार करना आवश्यक है।

पाँचवीं चुनौती कौशल असंगति है। रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों और युवाओं के कौशल के बीच अंतर को कम करना होगा। शिक्षा संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और उद्योग से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। छठी चुनौती तकनीकी परिवर्तन है। तकनीकी परिवर्तन से कुछ रोजगार समाप्त हो सकते हैं, लेकिन नए रोजगार भी पैदा होते हैं। इसलिए श्रमिकों को बदलती तकनीक के अनुरूप पुनःकौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करना आवश्यक है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत को रोजगार प्रधान विकास रणनीति अपनानी चाहिए। श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्रामीण उद्योगों का विस्तार, महिला रोजगार, युवा उद्यमिता, कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्र का विस्तार इस रणनीति के प्रमुख आधार हो सकते हैं।

13. निष्कर्ष

भारत में बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बाजार में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। 2017–18 से 2023–24 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में सामान्य स्थिति के आधार पर श्रम बल सहभागिता दर 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 60.1 प्रतिशत हुई। इसी अवधि में महिलाओं की सहभागिता 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई। यह वृद्धि भारत की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। अधिक लोगों का श्रम बाजार में शामिल होना आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना को बढ़ाता है। लेकिन श्रम बाजार में सहभागिता बढ़ना तभी वास्तविक आर्थिक लाभ में परिवर्तित होगा जब इन लोगों को पर्याप्त और उत्पादक रोजगार प्राप्त हो। 2025 के वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या की श्रम बल सहभागिता 59.3 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 62.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 52.2 प्रतिशत रही। महिलाओं की सहभागिता 40.0 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की 79.1 प्रतिशत। ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की अभी बड़ी संभावना मौजूद है।

भारत की रोजगार संरचना में कृषि का महत्व भी बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में देश के कार्यबल का लगभग 46.1 प्रतिशत लगा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण रोजगार और कृषि उत्पादकता में सुधार भारत की रोजगार नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बेरोजगारी का समाधान केवल रोजगार कार्यालयों अथवा सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगा। इसके लिए अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, विनिर्माण को रोजगार प्रधान बनाना, सेवा क्षेत्र का विस्तार करना, छोटे उद्योगों को मजबूत करना तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार नीति का अभिन्न अंग बनाना भी आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए पाठ्यक्रमों को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ना होगा। युवाओं को केवल शैक्षणिक ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण और कार्य अनुभव भी देना होगा। महिला रोजगार भारत के लिए विशेष अवसर प्रस्तुत करता है। महिलाओं की श्रम सहभागिता में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर अभी भी पर्याप्त है। यदि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और लचीले रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो भारत की कुल आर्थिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अतः भारत के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें **आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक**

समावेशन को एकीकृत रूप से देखा जाए। भारत की युवा जनसंख्या को यदि उचित शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यही जनसंख्या देश के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है।

14. अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य के अध्ययन की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों और सैद्धांतिक विवेचन पर आधारित है। इसमें प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए अध्ययन के निष्कर्ष उपलब्ध सरकारी आँकड़ों और प्रकाशित सामग्री की व्याख्या पर आधारित हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में रोजगार और बेरोजगारी मापने की अलग-अलग पद्धतियाँ हो सकती हैं, इसलिए अलग-अलग वर्षों के आँकड़ों की तुलना करते समय संबंधित परिभाषा और मापन पद्धति को ध्यान में रखना आवश्यक है। बेरोजगारी दर स्वयं रोजगार की पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती। किसी व्यक्ति के रोजगार में होने के बावजूद उसकी आय कम हो सकती है, रोजगार अस्थायी हो सकता है अथवा उसकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य के अध्ययन में बेरोजगारी दर के साथ रोजगार की गुणवत्ता, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की स्थिरता और उत्पादकता को भी शामिल किया जाना चाहिए। भविष्य में भारत के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। ग्रामीण और नगरीय रोजगार के बीच अंतर, युवा बेरोजगारी, महिला श्रम सहभागिता, शिक्षित बेरोजगारी और कौशल असंगति पर अलग-अलग अध्ययन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी परिवर्तन और स्वचालन का रोजगार पर प्रभाव भी महत्वपूर्ण शोध विषय हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण : वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24। (Ministry of Statistics)
2. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण : वार्षिक प्रतिवेदन 2025। (Ministry of Statistics)
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 : रोजगार एवं कौशल विकास। (India Budget)
4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 : कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ। (India Budget)
5. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत में श्रम एवं रोजगार संबंधी सांख्यिकीय प्रतिवेदन। (Ministry of Statistics)
6. भारत सरकार। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका संबंधी नीतिगत दस्तावेज।
7. भारत सरकार। कौशल विकास एवं उद्यमिता संबंधी नीतिगत दस्तावेज।
8. नीति आयोग। भारत में रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी अध्ययन।